



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1990/आषाढ़ 5, 1912

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1990/ASADHA 5, 1912

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1990

सा.का.नि. 600(अ) :—रेल रेट अधिकरण, माधारण
खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के
साथ पठित, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की
धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, और रेल रेट अधिकरण नियम, 1959 को अधि-
क्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित
विनियम बनाता है, अर्थात् :—

रेल रेट अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 1990

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का
संक्षिप्त नाम रेल रेट अधिकरण (प्रक्रिया) विनियम, 1990
है।

(2) यह अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त
होगे।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ
में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से रेल अधिनियम, 1989 (1989
का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “परिशिष्ट” से इन विनियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत
है;

(ग) “आवेदक” से धारा 45 के अंतर्गत आवेदन करने
वाला रेल प्रशासन अभिप्रेत है;

(घ) “अध्यक्ष” से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) “संहिता” से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
(1908 का 5) अभिप्रेत है;

(च) “परिवारी” के धारा 36 के अधीन परिवार करने
वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (छ) "मध्यक्षेपी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिकरण की इजाजत से किसी कार्यवाही में मध्यक्षेप करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो;
- (ज) 'सदस्य' से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) 'अभिवचन' से धारा 36 के अधीन कोई परिवाद, धारा 45 के अधीन कोई आवेदन, प्रत्यर्थी द्वारा इसमें से किसी का उत्तर, उत्तर का जवाब, जहां किसी अधिकरण द्वारा अनुज्ञात या निर्देशित किया गया हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मध्यक्षेपी द्वारा फाइल किए गए, यथास्थिति, समर्थन के आधार अथवा अक्षेप हैं।
- (ञ) 'कार्यवाही' से अधिकरण के समक्ष कार्यवाही अभिप्रेत है;
- (ट) 'निर्देश' से धारा 39 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकरण को किया गया कोई निर्देश अभिप्रेत है;
- (ठ) 'प्रतिनिधि' से लिखित रूप से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अन्तर्गत कोई विधि व्यवसायी है;
- (ड) 'प्रत्यर्थी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 36 के अधीन किसी परिवाद में या धारा 45 के अधीन किसी आवेदन में पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया है;
- (ढ) 'सचिव' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय, इन विनियमों के अधीन सौंपे गए कृत्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का जो समय-समय पर अधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएं, निर्वहन कर रहा है और इसके अन्तर्गत सहायक सचिव और अधिकरण द्वारा सचिव के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी भी है;
- (ण) 'धारा' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (त) 'अधिकरण' से धारा 33 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया रेल रेट अधिकरण अभिप्रेत है;
- (थ) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके इस अधिनियम में हैं;
- (द) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और इन विनियमों अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में हैं।

3. मुद्रण कला संबंधी विनिर्देशः—अधिकरण को प्रस्तुत किए गए सभी अभिवचन, शपथ पत्र और अन्तर्वर्ती आवेदन और उनकी प्रतियां सफेद पूर्ण आकार के फोलियों कागज पर टाइप की गई होंगी या साफ और स्पष्ट रूप से मुद्रित की गई होंगी, बायीं तरफ कम से कम 4 इंच चौड़ा हाशिया होगा और दायीं तरफ करीब 2.5 इंच चौड़ा हाशिया होगा और पृथक् शीटों साथ में जोड़ दी जाएंगी। टाइप लिपि या मुद्रण कागज के केवल एक तरफ होगा और क्रमिक रूप से संख्यांकित किए गए पंक्तियों में विभाजित होगा। तारीखें, जोड़ और संख्याएं स्पष्ट रूप से अंकों में वर्णित की जाएंगी :

4. प्रतिनिधि की नियुक्ति :—(1) कार्यवाही का कोई पक्षकार लिखित रूप से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष सभी अवसरों पर उपसंज्ञात होने, कार्य करने और मुने जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

परन्तु ऐसी नियुक्ति केवल उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको नियुक्ति आदेश सचिव के पास फाइल किया जाता है :

परन्तु यह और कि अधिकरण का कोई ऐसा सदस्य, जिसने ऐसे सदस्य के रूप में पद धारण किया है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) कोई ऐसी नियुक्ति अथवा प्रतिनिधि की नियुक्ति के निबन्धन उसे नियुक्त करने वाले पक्षकार द्वारा लिखित रूप से की गई घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत किए जा सकेंगे या उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा प्रतिसंहरण या पंजीन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह सचिव के पास फाइल नहीं कर दिया जाता है।

(3) संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 3 के उपबन्ध जहां तक हो सके, प्रतिनिधियों को लागू होंगे।

5. दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण, उपसंज्ञाति और कार्य करने वाला :—निम्नलिखित द्वारा किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे, उपांतज्ञात हुआ जा सकेगा अथवा कार्य किया जा सकेगा।

- (क) किसी फर्म की दशा में उसके भागीदार द्वारा;
- (ख) किसी निगमित निकाय, संगम अथवा प्राधिकरण की दशा में, यथास्थिति, उसके अध्यक्ष, समापति, प्रबन्धक निदेशक, महाप्रबन्धक अथवा सचिव द्वारा;
- (ग) रेल प्रशासन की दशा में उस रेल प्रशासन के महाप्रबन्धक या मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक या किसी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा; और
- (घ) केन्द्रीय सरकार की दशा में, सरकार के किसी सचिव या किसी नियुक्त सचिव या किसी उप सचिव या किसी अधर सचिव द्वारा और रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की दशा में रेल बोर्ड के

सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव या किसी कार्यपालक निदेशक अथवा किसी निदेशक, संयुक्त निदेशक या उप निदेशक द्वारा।

6. सत्यापन :—(1) प्रत्येक अभिवचन अभिवचन के पक्षकार या पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा अथवा अधिकरण के समाधानप्रद रूप से मामले के तथ्यों से सु-परिचित साबित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संबंधित पक्षकारों के प्रति निर्देश से वह विनिर्दिष्ट करेगा जो वह अपने ज्ञान के आधार पर सत्यापित करना है और जो वह प्राप्त की गई और सच होने के लिए विश्वास की गई जानकारी के आधार पर सत्यापित करना है।

(3) सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षरित किए जाएंगे और उसमें वह तारीख जितनी और वह स्थान जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, कथित होगा।

(4) जहां सत्यापन पक्षकार से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है वहां उसका नाम और पता उसके हस्ताक्षर के नीचे दिया जाएगा।

7. प्रस्तुति :—विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकरण के लिए आशयित सभी अभिवचन और दस्तावेज, आवेदन और संसूचनाएं अधिकरण के मुख्यालय में सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी अथवा रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएंगी।

8. प्रस्तुत करने के लिए समय :—(1) निश्चित समय के भीतर फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित या निर्देशित अभिवचन और अन्य दस्तावेज उस समय के भीतर अधिकरण के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे।

(2) अधिकरण के कार्यालय में प्राप्ति की तारीख को फाइल करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा।

9. सूचना की तामील और समन :—(1) अधिकरण या सचिव द्वारा जब तक अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो, यथास्थिति, पक्षकारों या साक्षियों को सूचनाओं और समनों की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अधिकरण को दिए गए पते पर की जाएगी।

(2) किसी पक्षकार को सूचना की तामील प्रतिनिधि पर भी की जा सकेगी।

10. कार्यवाही का प्रारंभ :—अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 36 के अधीन किसी परिवार द्वारा या धारा 45 के अधीन किसी आवेदन द्वारा या धारा 39 के अधीन किसी निर्देश द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी।

11. परिवार :—(1) धारा 36 के अधीन कोई परिवार अधिकरण को संबोधित होगा और लिखित रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा। उसमें परिवार का नाम

वर्णन और पूरा पता उपबणित होगा और यदि उस मामले में परिवार के लिए कोई प्रतिनिधि है तो उसका नाम और पूरा पता भी कथित होगा।

(2) परिवार में स्पष्ट और क्रमिक रूप से तथ्यों का विवरण, परिवार के आधार पर, वह अनुतोष या उन्वार जिसका परिवार दावा करता है और जहां रेल प्रशासन से अन्यथा किसी व्यक्ति को प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित करना चाहा गया हो वहां उसको अभियोजित करने के लिए आधार भी उपबणित होंगे।

12. परिवारियों का संयोजन :—(1) कार्यवाही में एक ही हिन रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति उस परिवार में संयोजन कर सकेंगे, जिस दशा में सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां उनके संयुक्त नामों में होंगी।

(2) जहां एक से अधिक परिवार है, वहां वे परिवार में परिवारियों में से किसी एक को या उसके प्रतिनिधि को उस व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित करेंगे, जिस पर किसी समन या सूचना की सभी परिवारियों के लिए और उनको और से तामील की जा सकेगी।

13. प्रत्यर्थी :—(1) जहां कोई परिवार रेल प्रशासन के विरुद्ध किया गया है, वहां ऐसे रेल प्रशासन का प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

(2) जहां परिवार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अन्य व्यक्ति पर उस अनुतोष से जो वह चाह रहा है, तारिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां ऐसे व्यक्ति को भी प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

(3) प्रत्यर्थी का नाम, वर्णन और पता परिवार में दिया जाएगा और जहां सरकारी रेल का कोई रेल प्रशासन प्रत्यर्थी है वहां संहिता की धारा 79 के उपबंध लागू होंगे।

14. परिवार की प्रतिया :—प्रत्येक परिवार के साथ उतने से दुगुनी प्रतियां होंगी जितने पक्षकार हैं और तीन अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के उपयोग के लिए होंगी।

15. फीस और जमा :—प्रत्येक परिवार के साथ परिवार 250 रुपए फीस का संदाय करेगा और अनंतिम रूप से 150 रुपए सूचनाओं की तामील और अन्य प्रक्रियाओं और अभिलेख-पुस्तिका के तैयार करने की लागत के प्रभाओं को पूरा करने के लिए जमा करेगा।

16. परिवार की संवीक्षा और रजिस्ट्रीकरण :—(1) किसी परिवार की प्राप्ति पर सचिव उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख चिह्नित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात् वह उस पर यह रिपोर्ट पृष्ठांकित करेगा कि प्रथम दृष्टया परिवार अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है अथवा नहीं।

(2) जहां सचिव पृष्ठांकित करता है कि परिवार अधिकरण की अधिकारिता के भीतर नहीं है वहां वह अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा।

(3) जहां कोई परिवार इन विनियमों के अनुसार नहीं है और उसके साथ आवश्यक फीस या जमा राशि नहीं है और परिवारी सचिव द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर दृष्टि को दूर नहीं करता है, वहां सचिव उसे यथासंभव शीघ्र अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा।

(4) सचिव फाइल किए गए सभी परिवारों को उस क्रम के अनुसार जिसमें वे उसने प्राप्त किए हैं, क्रम संख्याएं देगा और उन्हें परिशिष्ट-II के प्रप-1 में विनिर्दिष्ट किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।

17. परिवार का लौटाना :—(1) जहां अधिकरण की राय है कि परिवार प्रथम दृष्टया उसकी अधिकारिता से पर है वहां वह सचिव को परिवार को उस आशय के पृष्ठांकन के साथ लौटाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि ऐसे पृष्ठांकन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परिवारी अधिकारिता के प्रश्न पर सुने जाने के लिए कोई आवेदन करता है तो अधिकरण परिवारी और ऐसे अन्य पक्षकारों को, जो वह ठीक समझे, सुनने के पश्चात प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

(3) प्रत्यर्थी द्वारा संदत्त की गई फीस का प्रतिदाय कर दिया जाएगा यदि परिवार उसे विनियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप लौटाया जाता है।

18. पक्षकारों को जोड़ना और निकालना :—(1) अधिकरण, किसी प्रक्रम पर, सचिव की रिपोर्ट या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर, जो अधिकरण को उचित प्रतीत हों, आदेश दे सकेगा कि अनुचित रूप से संयोजित किया गया किसी पक्षकार का नाम, चाहे परिवारी के रूप में या प्रत्यर्थी के रूप में हो, काट दिया जाए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे चाहे परिवारी के रूप में या प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए, अथवा जिस पर मांगे गए अनुतोष का तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़ सकता हो अथवा अधिकरण के समक्ष जिसके उपसर्जित परिवार में अंतर्विलित प्रश्नों के न्यायनियर्णन के लिए उचित या आवश्यक समझी जाए, जोड़ दिया जाए।

परन्तु तथापि कोई भी व्यक्ति परिवारी के रूप में बिना उसकी सहमति के नहीं जोड़ा जाएगा।

(2) कोई कार्यवाही केवल पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगी।

(3) जब प्रत्यर्थियों को जोड़ा जाता है तब परिवार और रजिस्टर को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और परिवारी अपने परिवार की अतिरिक्त प्रतियां इतनी

संख्याओं में जितनी जोड़े गए प्रत्यर्थियों की संख्या के दुगुने के बराबर हो, फाइल करेगा।

19. परिवार की सूचना का तामील : (1) परिवार की प्रति प्रत्येक प्रत्यर्थी पर अधिकरण की मुद्रा से मुद्रांकित और सचिव के इस पृष्ठांकन के साथ तामील की जाएगी कि प्रत्यर्थी परिवार का अपना उत्तर ऐसी तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर फाइल करे और उसमें यह भी कथित होगा कि ऐसे उत्तर को उक्त कालावधि के भीतर फाइल किए जाने में व्यतिक्रम की दशा में अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवार सुनने के लिए अग्रसर हो सकेगा और यह भी कथित होगा कि ऐसे मामले में प्रत्यर्थी को अधिकरण की इजाजत के सिवाय और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिकरण अधि रोपित करना ठीक समझे, नहीं सुना जाएगा।

(2) किसी रेल प्रशासन की दशा में प्रति की संबंधित रेल के महाप्रबन्धक पर तामील की जा सकेगी।

(3) जहां अधिकरण की राय है कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है वहां एक लोक सूचना भी परिवारी के खर्चे पर और अधिकरण के सचिव द्वारा आदिष्ट रीति से प्रकाशित की जाएगी और उसमें परिवार फाइल करने पक्षकारों के नाम, अभियोजनों के संक्षिप्त विवरण और चाहे गए अनुतोष का वर्णन होगा तथा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो याचिका में चाहे गए अनुतोष के समर्थन में या उसके विरोध में मध्यक्षेप करने की इच्छा रखता हो, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिकरण को मध्यक्षेप करने की अनुमति देने के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) यदि यह समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु उनका कार्यवाही में वैसा ही हित है जो परिवारी या प्रत्यर्थी का है तो वह तथ्य लोक सूचना में वर्णित किया जाना चाहिए और ऐसी लोक सूचना के पश्चात अधिकरण द्वारा किया गया कोई विनिश्चय ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगा।

20. परिवार का वापस लिया जाना : (1) परिवारी परिवार के संस्थित किए जाने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपने परिवार को वापस ले सकेगा और उस मामले में अधिकरण खर्चे के बारे में आदेशों सहित ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) उत्तर फाइल किए जाने के पूर्व परिवार के वापस लेने की दशा में परिवारी द्वारा संदत्त की गई फीस का प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

21. परिवार का समझौता : जब किसी परिवार का पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा समायोजन किया जाता है तो दोनों पक्षकार तुरन्त अधिकरण को उसके बारे में सूचित करेंगे और अधिकरण, ऐसी सूचना के पश्चात

यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, परिवार का निपटारा करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

22. उत्तर: (1) उत्तर में उस परिवार में अन्तर्विष्ट तथ्यों के प्रत्येक अभिकथन को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार किया जाएगा या उससे इंकार किया जाएगा। और ऐसा परिवारों द्वारा अभिकथित आधारों के साधारण इंकार द्वारा नहीं किया जाएगा और जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा इंकार नहीं किया जाता है उब तक परिवार में तथ्य के अभिकथन को सामान्यतः प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया समझा जाएगा। उत्तर में उन तात्विक तथ्यों का स्पष्ट और प्रमित कथन होगा जिन पर प्रत्यर्थी भरोसा करता है और उसमें प्रतिरक्षा के सभी आधार होंगे।

(2) उत्तर क्रमिक रूप से संख्यांकित पैराग्राफों में विभाजित होगा और जिस पर हस्ताक्षर किए गए होंगे और वह सम्यक रूप से सत्यापित होगा और उसमें प्रत्यर्थी का नाम, वर्णन और पूरा पता उपवर्णित होगा और यदि मामले में प्रत्यर्थी के लिए कार्य करने वाला कोई प्रतिनिधि होगा तो उसका नाम और पूरा पता भीई अभिकथित होगा।

(3) प्रत्येक उत्तर के साथ जितने पक्षकार हैं उनसे दुगुनी प्रतियां होंगी और तीन अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के प्रयोग के लिए होंगी और 150 रुपए की राशि भी सूचना की तामील और अन्य प्रक्रियाओं के प्रभारों तथा अभिलेख प्रस्ताव के तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए जमा की जाएगी।

23. उत्तर की संवीक्षा और तामील :- (1) किसी उत्तर की प्राप्ति पर सचिव उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख चिह्नित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि उत्तर इन विनियमों के अनुसार नहीं है और उसके साथ आवश्यक जमा राशि नहीं है तथा प्रत्यर्थी सचिव द्वारा अनुशात समय के भीतर त्रुटि में सुधार नहीं करता है तो सचिव उसे यथासंभव शीघ्र अधिकरण में समक्ष आदेशों के लिए रखेगा।

(3) प्रत्यर्थियों से प्राप्त उत्तरों की प्रतियां मुद्रांकित की जाएंगी और सचिव द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उनकी परिवारों पर और ऐसे अन्य पक्षकारों पर, जिसका अधिकरण आदेश दे, तामील की जाएगी।

24. पश्चातवर्ती अभिवचन :- उत्तर के पश्चातवर्ती कोई अभिवचन अधिकरण की इजाजत पर के सिवाय और ऐसे निबन्धनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा किन्तु अधिकरण किसी समय किसी पक्षकार से जबाब या अतिरिक्त जबाब की उसकी उतने से दुगुनी प्रतियों के साथ, जितने पक्षकार हैं और अधिकरण के उपयोग के लिए तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ अपेक्षा कर सकेगा और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय नियत कर सकेगा।

25. अभिवचन का संशोधन :- अधिकरण किसी प्रक्रम पर किसी अभिवचन को संशोधित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और किसी ऐसे विषय को, जिसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जो मामले की उचित सुनवाई को उलसन में डालता हो या उसमें विलंब करता हो, हटाए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवादों पर वास्तविक प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

26. दस्तावेजों का पेश किया जाना :- (1) जब तक कि अर्च्छा हेतुक दक्षित नहीं किया जाता है और ऐसे निबन्धनों पर जो अधिकरण ठीक समझे, किसी पक्षकार के कब्जे में के ऐसे सभी दस्तावेज, जिन पर वह सुनवाई में भरोसा करने की इच्छा करता है, उनके द्वारा उनकी सूची सहित ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो अधिकरण द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियत की जाए, पेश किए जाएंगे। वह उन्नी समय दस्तावेजों की उतनी प्रतियां फाइल करेगा, जितने पक्षकार हैं और तीन अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के प्रयोग के लिए फाइल करेगा।

(2) अधिकरण किसी समय किसी पक्षकार द्वारा प्रयुक्त मामले से संबंधित उसके कब्जे या शक्ति में के ऐसे दस्तावेज, जो वह ठीक समझे, पेश करने का आदेश दे सकेगा।

27. परिप्रश्न और प्रकटीकरण :- कार्यवाही का कोई पक्षकार अधिकरण को विरोधी पक्षकार की परीक्षा के लिए लिखित रूप में परिप्रश्न परिदत्त करने की इजाजत के लिए अथवा विरोधी पक्षकारों को अपने कब्जे में के दस्तावेजों का प्रकटीकरण करने का निर्देश देने वाले के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और किसी भी दशा में संहिता को प्रथम अनुसूची के आदेश II के उपबंध जहां तक हो सकेगा लागू होंगे और ऐसे आवेदन नामजूर किए जा सकें यदि उनमें इतना विलंब हो जाता है कि जिससे मामले की सुनवाई का स्थगन करना आवश्यक हो जाए।

28. दस्तावेजों का निरीक्षण :- (1) कोई भी पक्षकार किसी भी समय उस दूसरे पक्षकार को, जिसके अभिवचनों या शपथ पत्रों में किसी दस्तावेज का निर्देश किया गया है सूचना देने का हकदार होगा और ऐसी सूचना ऐसा दस्तावेज सूचना देने वाले पक्षकार के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने को बाधन और उनकी प्रतियां लेने की अनुज्ञा देने के लिए होगी और ऐसी सूचना का अनुपालन नहीं करने वाला पक्षकार पश्चातवर्ती किसी ऐसे दस्तावेज को अपनी ओर से साक्षा में रखने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि वह अधिकरण का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसके पास ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) अधिकरण के समक्ष चाहे स्वेच्छिक रूप से या अध्यक्षता पर, पेश की गई सभी पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं का, पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा :

परन्तु अधिकरण अपने विवेकानुसार पुस्तकों, दस्तावेजों और वस्तुओं के ऐसे भागों के प्रकाशन से इंकार कर सकेगा :

जिन का प्रकाशन पक्षकार अपने हित के प्रतिकूल होने वाले बताएँ।

29. विवादों की विरचना :— (1) अभिवचनों की समाप्ति और दस्तावेजों के फाइल करने के पश्चात् अधिकरण पक्षकारों या प्रतिनिधियों से प्रारूप विवादक देने की अपेक्षा करेगा।

(2) तदुपरि अधिकरण विवादों की विरचना करेगा ;

(3) जहाँ अधिकरण की राय है कि विवादक किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके समक्ष नहीं है, परीक्षा के बिना अथवा पेश न किए गए कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण के बिना ठीक से विरचित नहीं किया जा सकता है वहाँ वह तत्समयप्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हाजिरी की अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कसी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश कर सकेगा।

30. सुनवाई के पूर्व पक्षकारों की परीक्षा :— अधिकरण परिवार की सुनवाई के पूर्व निम्नलिखित पर विचार करने के प्रयोजन के लिए पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की परीक्षा कर सकेगा—

- (क) पक्षकारों के बीच विवाद विषयों का सरलीकरण, संक्षेपण या समायोजन ;
- (ख) प्रत्येक पक्षकार द्वारा दूसरे के दस्तावेजों को स्वीकार करना या उनसे इंकार करना ;
- (ग) साक्षियों की संख्या की सीमा ;
- (घ) सुनवाई पर प्रक्रिया ; और
- (ङ) ऐसे अन्य विषय जो परिवार का शीघ्र निपटारा करने में सहायता कर सकेंगे।

31. विवादों का संशोधन :—अपना विनिश्चय करने के पूर्व किसी भी समय अधिकरण विवादों में संशोधन कर सकेगा या एस अतिरिक्त विवादों की विरचना कर सकेगा जो वह पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त विषयों का अवधारण करने के लिए ठीक समझ या जो आवश्यक हो और वह किसी भी ऐसे विवादक को निकाल सकेगा जो उसे गलत रूप से विरचित किया गया प्रतीत हो।

32. मध्यक्षेपी :—(1) विनियम 19 के उप-विनियम (3) के अधीन दी गई लोक सूचना पर कोई व्यक्ति उक्त उप विनियम में विहित समय के भीतर परिवार में चाहे गए अनुतोष के समर्थन में या उसके विरोध में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए अधिकरण को अर्जी दे सकेगा।

(2) मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए अर्जी में प्रस्थापित मध्यक्षेप के आधार, कार्यवाही में अर्जीदार की स्थिति और उसका हित और यह कि वह चाहे गए अनुतोष के समर्थन में है या उसके विरोध में, उपवर्णित होना चाहिए।

(3) यह अधिकरण के विवेक पर होगा कि वह पक्षकारों को जोड़ने से संबंधित विनियम 18 के उप विनियम

(1) के उपबन्धों के आधार पर ऐसी इजाजत दे या उसे नामंजूर कर दे।

(4) यदि इजाजत दे दी जाती है तो अर्जीदार को मध्यक्षेपी के रूप में संयोजित किया जाएगा और उसे उसकी सूचना दी जाएगी तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर वह अपना अभिवचन फाइल करेगा जो, यथा-स्थिति, विनियम 11 के उप विनियम (2) अथवा विनियम 22 के उप विनियम (1) के उपबन्धों के अनुरूप होगा। वह उसी समय सूचना की तामील अन्य कार्यवाहियों के खर्चों को और अभिलेख पुस्तिका तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए 150 रुपए और यदि वह परिवार के समर्थन में मध्यक्षेप करता है तो 250 रुपए की राशि जमा करेगा। वह अपने अभिवचनों की उतने से दुगुनी प्रतियाँ जितने पक्षकार हैं और तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अधिकरण के प्रयोग के लिए फाइल करेगा।

33. सुनवाई की तारीख :—विवादों के परिनिर्धारण के पश्चात् अधिकरण परिवार की सुनवाई के लिए दिन, समय और स्थान नियत करेगा और उसकी सूचना संबंधित पक्षकारों को देगा।

34. सुने जाने का अधिकार :—(1) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का कोई पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा सुने जाने का हकदार होगा।

(2) अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सहायक होने की संभावना है अधिकरण को संवोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

35. स्थानीय जांच और रिपोर्ट :—किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें अधिकरण स्थानीय जांच को अपेक्षित और उचित समझता है, कि वह किसी रेल अधिकारी को जो किसी सहायक अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् स्थानीय जांच करने के लिए और उस पर अधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए नियत कर सकेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति के बारे में पक्षकारों को नियत समय के भीतर, रिपोर्ट का निरीक्षण करने के पश्चात् अपने आक्षेप यदि कोई हों, फाइल करने के लिए संयोजित किया जा सकेगा और अधिकरण इन आक्षेपों का निपटारा करेगा।

परन्तु वह उक्त समय के भीतर फाइल न किए गए किसी आक्षेप पर विचार करने से इंकार कर सकेगा। रिपोर्ट को उस मामले में साक्ष्य का भाग माना जाएगा। संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 26 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, ऐसी स्थानीय जांचों और रिपोर्टों को लागू होंगे।

36. कमीशन :—अधिकरण कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा। संहिता के आदेश 26 के उपबन्ध जहाँ तक हो सके, इन विनियमों के अधीन निकाले गए कमीशन को लागू होंगे।

37. साक्षियों को मगन :—(1) कोई पक्षकार, जो अधिकरण के समक्ष या विनियम 36 के अधीन नियुक्त किए

गए आयुक्त के समक्ष उपसजाती के लिए साक्षी को समन करने की इच्छा रखता है, सुनवाई की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिन की हाजिरी अपेक्षित है। सूची में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, वर्णन और पता और यह कि वह विशेषज्ञ के रूप में या अन्यथा साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, वर्णित होगा और अन्त में की तारीख, यदि कोई हो विनिश्चित करते हुए मामला और दस्तावेज का वर्णन जिससे उन्हें पहचाना जा सके, होगा। वह ऐसी सूची के साथ उन भत्तों की जिनके उक्त व्यक्ति यात्रा और अधि-करण के समक्ष हाजिरी के लिए हकदार हैं, कुल रकम, जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उसकी मामूली आर्थिक सिविल अधिकारिता में परिगणित की गई हो, जमा करेगा।

(2) जब कभी अधिकरण यह आवश्यक समझे तो वह स्वप्रेरणा से किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने अथवा उसके कब्जे में के किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को समन करने के खर्चों के बारे में आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा।

(3) साक्षियों को विनियम 9 के उप विनियम (1) के अनुसार नियत समय और स्थान पर हाजिर होने की अथवा दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करने वाली समनों की तामील की जाएगी। यदि कोई साक्षी जिस पर इस प्रकार तामील की गई है या अपेक्षित हाजिर होने में असफल होता है तो उसको संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश, 26 के उपबन्धों का आश्रय लेकर हाजिर कराया जा सकेगा।

38. और साक्ष्य :—अधिकरण सुनवाई के किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार से किसी विवाद पर और साक्ष्य के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

39. प्रारम्भिक विधि प्रश्न :—अधिकरण किसी कार्यवाही के पक्षकारों की सम्पत्ति में या किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अभिवचनों द्वारा उठाए गए किसी विधि के प्रश्न को सुनवाई के लिए रखे जाने और परिवार की सुनवाई के पूर्व किसी समय निपटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा। यदि अधिकरण की राय में ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय सारभूत रूप से सम्पूर्ण परिवार का निपटारा करता है तो अधिकरण ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो।

40. सुनवाई :—(1) प्रत्येक परिवार अधिकरण द्वारा नियत किए गए समय और स्थान पर खुले न्यायालय में सुना जाएगा।

(2) सुनवाई प्रति दिन, जहां तक अधिकरण की विवेक-बुद्धि से व्यवहारिक और सुविधाजनक हो आगे चलेगी और उसे किसी पत्रकार की प्रेरणा पर, अधिकरण द्वारा पर्याप्त समझे गए कारणों और ऐसे निबन्धनों पर के सिवाय, जिनके

अन्तर्गत खर्चों का संदाय है, जिन्हें अधिकरण ठीक सत्ते स्थगित नहीं किया जाएगा।

41. उपसजाति में व्यक्तिक्रम :—यदि परिवारी सुनवाई के लिए नियत किए गए समय और स्थान पर उपसजात नहीं होता है तो अधिकरण परिवार को खारिज कर सकेगा अथवा अपने विवेकानुसार परिवार का समर्थन करने वाले किसी मध्य श्रेणी की प्रेरणा पर सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और यदि प्रत्यर्थी उसी प्रकार उपसजात नहीं होता है तो अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवार को सुनवाई कर सकेगा और विनिश्चय कर सकेगा यदि सुनवाई की किसी स्थगित तारीख पर पक्षकार या उनमें से कोई उपसजात नहीं होता है तो अधिकरण यथास्थिति परिवार को खारिज कर सकेगा अथवा उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा अथवा उनकी अनुपस्थिति में मामले का निपटारा कर सकेगा।

42. पुनः सुनवाई :—(1) जब परिवार व्यक्तिक्रम के लिए खारिज किया जाता है किन्तु परिवारी अधिकरण का समाधान कर देता है कि व्यक्तिक्रम के लिए पर्याप्त हेतुक था तो खारिज का आदेश, विरोधी पक्षकार को सूचना के पश्चात्, जहां आवश्यक हो, अग्रस्त किया जा सकेगा और परिवार पर खर्चों के बारे में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जब कोई एक पक्षीय विनिश्चय किया जाता है किन्तु प्रत्यर्थी अधिकरण का समाधान कर देता है कि सूचना की उप पर सम्पत्ति रूप से उसे तामील नहीं की गई थी अथवा यह कि उसे सुनवाई में उपसजात होने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो एक पक्षीय विनिश्चय अग्रस्त किया जा सकेगा और मामले पर खर्चों के बारे में अथवा अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें अधिकरण ठीक समझे, आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) परिवार के खारिज करने का आदेश अथवा कोई एकपक्षीय विनिश्चय अग्रस्त करने के लिए आवेदन यथास्थिति परिवार के खारिज किए जाने के अथवा एक पक्षीय विनिश्चय धारित किए जाने के तीस दिन के भीतर किया जाएगा जब कि अधिकरण पर्याप्त कारणों के लिए विलंब के लिए माफी न दे दे।

43. 1872 के अधिनियम 1 का लागू होना :— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, कार्यवाहियों को लागू होंगे।

परन्तु अधिकरण स्वविवेक से पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवश्यक साक्ष्य सत्ते रूप से और शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपने उपबन्धों में से किसी को शिथिल कर सकेगा।

44. शपथ पत्र (1) किसी परिवार की सुनवाई पर साक्ष्य शपथ पत्र पर या मौखिक रूप से अथवा भागतः शपथ पत्र और भागतः मौखिक रूप से लिया जा सकता है।

परन्तु यदि कोई भी पक्षकार शपथ पत्र द्वारा किसी भाग पर भरोसा करने का आशय रखता है तो वह सुनवाई के कम से कम 10 दिन पूर्व दूसरे पक्षकार को प्रयोग किए जाने के लिए आशयित शपथ पत्र की एक प्रति परिदत्त करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा, जिसमें असफल होने पर उसे उसका प्रयोग अधिकरण की विशेष इजाजत से ही करने की अनुज्ञा दी जाएगी, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी पक्षकार, प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी शपथ पत्र की किसी प्रति की प्राप्ति के पश्चात् 7 दिन के भीतर दूसरे पक्षकार को प्रति परीक्षा के लिए परिवाद की सुनवाई में पेश किए जाने के लिए अभिसाक्षी से अपेक्षा करने वाली सूचना प्रदत्त करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा और जब तक कि अभिसाक्षी इस प्रकार पेश नहीं किया जाता है, तब तक उसके शपथ पत्र का प्रयोग अधिकरण की विशेष इजाजत से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) अधिकरण पर्याप्त हेतु से किसी भी समय आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकेगा अथवा यह कि किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई के समय ऐसी शर्तों पर, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे, पढ़ा जा सकेगा ;

परन्तु जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई भी पक्षकार प्रति परीक्षा के लिए किसी साक्षी के पेश किए जाने की संभावनी इच्छा रखता है और यह कि ऐसे साक्षी को पेश किया जा सकता है वहां ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया जाना प्राविष्ट करने वाला कोई आदेश लिया नहीं किया जाएगा।

(4) कोई भी शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा जो साक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में समर्थ है सिवाय अन्तर्धर्ती कार्यवाहियों में जिनमें उसके विश्वास के बारे में कथन उसके आधारों सहित स्वीकार किए जा सकेंगे।

(5) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में दिए जाने वाले किसी शपथ पत्र के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष अधिकरण के किसी पदाधिकारी को शपथ पत्र के अभिसाक्षी को शपथ दिखाने के लिए मण्डल कर सकेगा।

45. मौखिक साक्ष्य :- किसी साक्षी का मौखिक साक्ष्य अधिकरण के निदेशाधीन अंग्रेजी में खुले न्यायालय में लिया जाएगा और टाइप की हुई प्रति पर अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) जब साक्ष्य साक्षी द्वारा अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया जाता है तो अधिकरण किसी दुभाषिए को नियुक्त करेगा जो शपथ लेगा या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करेगा कि वह साक्ष्य का अंग्रेजी में सही रूप से अनुवाद करेगा दुभाषिए को ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो अधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए।

46. निर्णय :- (1) अधिकरण साक्ष्य और तथ्य सुनने तथा उन पर विचार करने के पश्चात्, या तो तत्काल या यथासाध्य शीघ्रता से कि भविष्यवर्ती दिन को अपना विनिश्चय देगा और जब विनिश्चय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाता है तब अधिकरण उस प्रयोजन के लिए एक दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों को या प्रतिनिधियों को दी जाएगी।

(2) विनिश्चय पर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और विनिश्चय के प्रभावो भाग की एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

47. खर्चे :- (1) अधिकरण अपने विवेकानुसार किसी पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को पूर्णतः या भागतः कार्यवाहियों के खर्चों का संदाय किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। यह तथ्य कि अधिकरण के पास कार्यवाहियों के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई वर्णन नहीं होगा।

(2) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लिए और उनके संबंध में खर्चों के अधिनियम के लिए अनुज्ञेय फीस का मापमान वह होगा जो परिशिष्ट 1 में वर्णित किया गया है।

(3) खर्चों का बिल सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और अधिकरण के विनिश्चय के साथ संलग्न किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पक्षकारों को भेजी जाएगी। खर्चों के बिल में, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार के कथन पर सचिव या अधिकरण द्वारा संशोधन किया जाएगा।

48. अधिकरण के कार्मिकों में परिवर्तन :- जहां अधिकरण अपने समक्ष किसी कार्यवाही को समाप्त करने में अपने कार्मिकों में किसी परिवर्तन के कारण विकारित रहता है वहां उत्तरवर्ती पुनर्गठित अधिकरण उसे उय प्रक्रम से पुनः आरम्भ कर सकेगा जिस पर पूर्व अधिकरण ने उसे छोड़ा था और वह कोई ऐसा विनिश्चय दे सकेगा या लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा जो उसके पूर्ववर्ती द्वारा नहीं किया गया है या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, और अतः पूर्ववर्ती द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय में संबंधित खर्चों के बिल का संशोधन कर सकेगा।

49. त्रुटियों का पुद्धिकरण :- अधिकरण को किसी विनिश्चय या आदेश में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न हुई त्रुटियों को या तो स्व-प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर अधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

50. अधिकरण किसी भी समय और खर्चों के बारे में या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या गलती का संशोधन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही में उठाए गए या उस पर आधारित

किमी) सार्वजनिक विवादों के लिए प्रत्यक्ष अवधारण करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

51. असाधारण आदेश :- अधिकरण ऐसे अन्तर्गत अधिकारों की जिसके अन्तर्गत असाधारण आदेश भी है, जो आवश्यक हो, मुद्राई करने के पश्चात् या एकपक्षीय रूप से उन्हें पारित कर सकेगा, उनमें फौजदारी कर सकेगा या उन्हें अपास्त कर सकेगा।

52. समय का विस्तारण या स्थगिकरण :- अधिकरण ऐसे विवादों पर जो मामले के न्याय में अपेक्षित हो, कोई कार्य करने या कोई कार्यवाही करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकेगा या कम कर सकेगा :-

परन्तु परिवाद या एकपक्षीय विनिश्चय की स्वीकृति करने के आदेश को अपस्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विहित अवधि को स्थगिकृत नहीं किया जाएगा।

53. समय की संगणना :- ऐसे सभी मामलों में जिन में दिनों को एक विशिष्टि मख्या इन विनियमों द्वारा या सर्विच या अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में विहित की गई है तो उसकी गणना प्रथम दिन का अपवर्जन करके और अन्तिम दिन को सम्मिलित करके की जाएगी और यदि अधिकरण का कार्यालय अन्तिम दिन बंद रहता है तो समय की गणना उस दिन का भी अपवर्जन करके की जाएगी। यदि किसी ऐसे दिन जिस दिन किसी पक्षकार द्वारा कोई कार्य किया जाता अपेक्षित है और कार्यालय उस दिन बंद रहता है, तो यह उस दिन किया जा सकेगा जिस दिन कार्यालय अपनी ओर खुलेगा।

54. धारा 45 के अधीन आवेदन - ये विनियम, जहां तक हो सके, वहां मामलों के निपटाए जाने पर लागू होंगे जहां कोई रेल प्रशासन धारा 45 के अधीन आवेदन है।

55. निर्देश :- जांच और रिपोर्ट के लिए अधिकरण का कोई आदेश अधिकरण के सचिव की सम्बंधित किसी पत्र के प्रथम में होगा और रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा। पत्र में प्रत्येक वादों के साथ-साथ, निम्नलिखित का निर्देशन होगा:

(क) जांच और रिपोर्ट के लिए अधिकरण का निर्देशन मामले के रूप में, और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कब्जे में की ऐसी सब जानकारी जिसे वह सरकार अधिकरण के समक्ष मामले के लिए सहायक समझती है।

56. जांच की सार्वजनिक सूचना :- अधिकरण किसी भी प्रश्न पर जांच में जापन प्रस्तुत करने या मौखिक जांच देने के लिए मामले में विवाद व्यापारियों या व्यापार संगठनों या व्यक्तियों या समर्थनानों के लिए उसके संबंध में साधारण तथा जांच के बारे में या किसी कार्यवाही के बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित कर सकेगा।

57. सार्वजनिक जांच :- अधिकरण के स्वविवेक पर सार्वजनिक जांच सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित किसी स्थान और स्थान पर की जा सकेगी।

58. जांच की रिपोर्ट :- जांच की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, और वह सरकार यदि वह ठीक समझती है, तो उसे जनता को उपलब्ध करायेगी।

59. जांच आयोग :- जांच के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण ऐसे कमीशन तैयार करेगा और ऐसे मामलों को समन कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

60. अभिलेख पुस्तिका :- किसी परिवाद या आवेदन में संबंधित प्रत्येक मामले में अभिलेखन, विवादों, अभिलेखित साक्ष्य, गृहीत दस्तावेजों और अभिलेख के ऐसे भागों की जिनके बारे में विनिर्दिष्ट रूप से यह आदेश किया गया है कि वे अभिलेख पुस्तिका का भाग रूप हैं, टंकण की गई अभिलेख पुस्तिका तैयार की जाएगी। ऐसे अभिलेख पुस्तिकाओं की उनकी प्रतियां तैयार की जाएंगी, जिनकी अधिकरण के सदस्यों और पक्षकारों के लिए अपेक्षित हो। अभिलेख पुस्तिकाओं के तैयार किए जाने का खर्च ऐसे मामले की वाहन या अधिकरण के कार्यालय में टंकित किया जाएगा, 1.75 भाग प्रति पृष्ठ के हिसाब में प्रभावित किया जाएगा।

61. अधिकरण के कार्यकरण के घंटे :- शनिवारों, रविवारों और अन्य सार्वजनिक अवकाश, के दिनों को छोड़कर और अवकाश द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए अधिकरण के कार्यकरण के घंटे पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 2.15 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक होंगे और अधिकरण के कार्यालय का समय पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगा।

62. साप्ताहिक अवकाश और दीर्घवकाश :- अधिकरण वैसे ही साप्ताहिक अवकाश और दीर्घवकाश मानेगा जैसे मद्रास उच्च न्यायालय मानता है।

परन्तु कार्यालय अवकाश के दौरान खुला रहेगा और अपना सामान्य कामकाज करेगा।

परन्तु यह और कि मात्र इस आधार पर कि अधिकरण अवकाश के दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, समय का कोई विस्तारण संजूर नहीं किया जाएगा।

63. दस्तावेजों की वापसी :- (1) साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों को कार्यवाहियों के निपटाए जाने के पश्चात् संबंध पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके वापस लौटाया जाएगा या उसे रसीद डाक द्वारा लागत या उसकी अपनी जोखिम और लागत पर पामेल द्वारा भेजा जाएगा।

परन्तु साक्ष्य में गृहीत किसी दस्तावेज को इससे पहले भी वापस लौटाया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने

वाला पक्षकार तस्विक को मूल प्रति के स्थान पर रखी गई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देना है और ऐसी अपेक्षा होने पर मूल प्रति प्रस्तुत करने का बचनबंध करना है।

(2) जहाँ कोई दस्तावेज किसी पक्षकार को उसे परिदत्त करके वापस लौटा दी जाती है वहाँ उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी एक रसीद ली जाएगी।

(3) माध्य में अपेक्षित दस्तावेज अभिलेख का भाग नहीं होंगे और वे उप-विनियम (1) में अपेक्षित रीति में क्रमशः उनके प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को वापस लौटा दिए जाएंगे।

64. अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ :— जब तक की अधिकरण द्वारा विशेष रूप से अन्यथा आदेश न दिया जाए, किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार कार्यवाहियों के अभिलेख के किसी भाग की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ अधिकरण के कार्यालय में तैयार की जाएंगी और उनके लिए ऐसी दर पर जिन पर मद्रास उच्च न्यायालय में प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रभार लिया जाता है, प्रभार लिया जाएगा।

65. प्रेषण :— अधिकरण का संदल या उसके पास निक्षिप्त सभी धन नकद रूप में अधिकरण के कार्यालय में संदल किया जाएगा या धनादेश द्वारा सचिव, रेल अधिकरण मद्रास के नाम में या रेखांकित डाक आदेश या रेखांकित बैंक

आदेश द्वारा एक व्यक्ति, इच्छित बैंक, मद्रास के नाम में प्रेषित किया जाएगा।

66. निक्षेपों के विस्तृत प्रतिदाय या वसूली :— किसी मामले की समाप्ति के पश्चात्, सचिव प्रत्येक पक्षकार द्वारा किए गए निक्षेप में से खर्च की गई रकम की संगणना करेगा और यथास्थिति, अधिक रकम को उसे वापस लौटा देगा या कम रकम की उमसे वसूली करेगा।

67. प्रथम और रजिस्टर :— तामील की जाने वाली सूचनाएँ और अधिकरण के कार्यालय में बताने रखे जाने वाले रजिस्टर और अन्य अभिलेख ऐसे होंगे जो परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

68. मद्रास उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम : मद्रास उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों का, जहाँ तक वे अधिनियम और इन विनियमों में असंगत नहीं हैं, अधिकरण के विश्लेषकानुसार पालन किया जा सकेगा।

69. न्यायालय की मुद्रा :— अधिकरण की मुद्रा सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

[मं. टी.सी.आई./89/216/2]

के. राजगोपालन नायर, महायुक्त सचिव,
रेल दर अधिकरण

परिशिष्ट 1

[विनियम 47 (2) देखिए]

अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में खर्चा देने के लिए फीस का मागमान

रु.

धारा 36 के अधीन परिवार, धारा 45 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए या परिवार के समर्थन में मध्यक्षेप के लिए	250.00
वकायतनामा के लिए	5.00
कोई अन्य आवेदन फाइल करने के लिए	3.00
सूचना, सभन की तालीम के लिए	5.00
परिग्रस्त की तामील के लिए	5.00
अधिकरण के बाहर किए गए शपथ पत्र फाइल करने के लिए	5.00
व्यादेश अर्जी के लिए	10.00
अधिकरण न्यायालय के किसी अधिकारी को समक्ष शपथ-पत्र देने के लिए	5.00

परिशिष्ट 2

ग्रन्थ 1

वर्ष का परिवार रजिस्टर

[विनियम 16 (4) देखिए]

क्रम सं.	परिवार की शीर्षक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	परिवार की तारीख	प्रत्यर्थी का नाम	विषय वस्तु	मध्यक्षेप का नाम	निर्णय की तारीख	निर्णय का प्रभाव	प्रभावी भाग	उच्च न्यायालय को रिट या प्रार्थना	प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई है
									पक्षकारों को संसूचित करने की तारीख	उच्चतम न्यायालय को अपील या संशोधन तथा परिणाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

परिशिष्ट 2

प्रकरण 2

वर्ष का आवेदन रजिस्टर

[विनियम 16 (4) और विनियम 51 देखिए]

क्रम आवेदन सं. की ओर उसकी प्राप्ति की तारीख	रजिस्ट्री- करण की तारीख	आवेदक का नाम	प्रत्यर्थी का नाम	मूल ताम्रपत्रों के प्रति निर्देश	मध्यस्थों का नाम	निर्णय की तारीख	निर्णय का प्रभावी भाग	का प्रभावी भाग के पक्षकारों को संसूचित करने की तारीख	प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई है	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

वर्ष का प्रकीर्ण/मध्यस्थ आवेदन रजिस्टर
(विनियम 51 देखिए)परिशिष्ट 2
प्रकरण 3

क्रम सं.	आवेदन की ओर उसको प्राप्ति की तारीख	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	आवेदक का नाम	प्रत्यर्थी का नाम	विषय वस्तु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मूल परिवार/आवेदन को प्रतिनिधित्व	मध्यस्थों का नाम	आदेश की तारीख	आदेश का प्रकार	आदेश को पक्षकारों को संसूचित करने की तारीख	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

वर्ष का निर्देश रजिस्टर

परिशिष्ट 2

प्रकरण 4

(विनियम 55 देखिए)

क्रम सं. निर्देश को विनिर्दिष्टता और उसको प्राप्ति की तारीख	रजिस्ट्रेशन की तारीख	निर्देश का विषय वस्तु	अधिकरण को रिपोर्ट की तारीख	सिफारिश	रिपोर्ट भेजने की तारीख	टिप्पणिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)						

परिशिष्ट 2

(विनियम 18 देखिए)

प्रस्ताव 5

रेल्वे रेट अधिकरण मद्रास के समक्ष

19-वां परिशिष्ट में

वर्तमान

परिशिष्ट

प्रस्ताव

सेवा में

में के विरुद्ध के द्वारा उपरोक्त परिशिष्ट सम्बन्धित किया है और यह उचित या आवश्यक प्रतीत होता है कि अधिकरण को परिशिष्ट में प्रस्तावों के प्रत्येक का अन्वेषण करने और विनिश्चय करने में समय बचाने के लिए उक्त मामलों में आपको परिशिष्टों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अतः सूचित किया जाता है कि रेल्वे रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 18 के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप परिशिष्ट में 19-वां को आप यह बचाने के लिए इस अधिकरण में समक्ष उपस्थित करें कि आप इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के लिए सहमत हैं या नहीं। आज तारीख 19-वां को में प्रस्तावों में और 3. डिसेम्बर को रेट रोज, मद्रास 105 दिनां अधिकरण को सूत्रा लगाकर दिया गया।

सचिव

रेल्वे रेट अधिकरण

परिशिष्ट 2

प्रस्ताव 5

(विनियम 19 देखिए)¹

रेल्वे रेट अधिकरण मद्रास के समक्ष

19-वां परिशिष्ट/आवेदन में

वर्तमान

परिशिष्ट/आवेदक

प्रस्ताव

सेवा में

रेल्वे रेट अधिकरण विनियम 1990 के विनियम 19 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप संलग्न परिशिष्ट/आवेदन की सामग्री को तारीख से 30 दिनों के भीतर उस पर अपना उत्तर-वाक्यों के साथ दायित्व करें तथा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त समय के भीतर ऐसा उत्तर देने में अग्रिम को यथा में अधिकरण परिशिष्ट/आवेदन आपको अनुमति में सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

आपका उत्तर और उसी प्रतियों मद्रास स्थित में कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे या रजिस्ट्रार ऑफ़ में भेजी जाएंगे। आपको सूचना की तारीख, यदि और अभिलेख पुस्तक की तारीख के लिए प्रस्तावों के रूप में 150 रुपए की राशि अंतर्गत रूप में भेजा करनी होगी। यह रकम या तो नकद में या मनोप्राप्ति से सचिव, रेल्वे रेट अधिकरण, मद्रास का भेजी होगी अथवा कान पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के अर्थ में प्रेषित की जायेगा के दक्षिणी रेल, मद्रास के पक्ष में होगी, भेजी होगी।

आज तारीख 19-वां का में प्रस्तावों में और 3. डिसेम्बर को रेट रोज, मद्रास 105 दिनां अधिकरण को सूत्रा लगाकर दिया गया।

सचिव

रेल्वे रेट अधिकरण

परिशिष्ट 2

(अंश 2)

[विनियम 19 (3) और (4) अन्तर्गत]

रेल रेट अधिकरण मद्रास के समक्ष

19-का परिवार/आवेदन नं.

परिवारी/आवेदक

बनाम

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 परिवार/आवेदक ने यह परिवार/आवेदन दिया है कि-----

आप यह विश्वास किया गया है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो आदेश में नहीं हैं, किंतु उनका भी इन कथनों में बड़ा हिस्सा है जो आप नामों परिवार/आवेदक या प्रत्यर्थी का है ;

अतः रेल रेट अधिकरण विनियम 1990 के विनियम 19 के उपविनियम (3) और उपविनियम (4) के अंतर्गत यह लोक सूचना दी जाती है जिसमें कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कथन चाहता है, इस सूचना के प्रकाशन के तीसरे दिन के अंतर्गत परिवार/आवेदन में शामिल होने के समर्थन या विरोध में मध्यस्थ करने या परिवारी/आवेदक अथवा प्रत्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने के लिए अधिकरण को अर्जी दे सके, जिसमें प्रस्तावित मध्यस्थ के आदेश के अंतर्गत उनके मामले में एक पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के आदेशों पर कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और हिस्सा उपस्थित होंगे।

ऐसा लोक सूचना के अंतर्गत अधिकरण द्वारा किया गया किंतु वह ऐसे मामलों पर कार्य करता है।

आज यह आरोप-----को मंत्र हस्ताक्षर से आरंभ में 3, विक्टोरिया क्रिकेट ग्राउंड, मद्रास-105 में किया अधिकरण को मद्रास न्यायालय दिया गया है।

निर्वाह,

मद्रास रेल रेट अधिकरण

परिशिष्ट 2

(अंश 3)

[विनियम 29 (2) अन्तर्गत]

रेल रेट अधिकरण मद्रास के समक्ष

19-का परिवार/आवेदन नं.

परिवारी/आवेदक

बनाम

प्रत्यर्थी/मध्यस्थ

संज्ञा में,

श्री-----परिवारी/आवेदक

प्रत्यर्थी/मध्यस्थ

अधिकरण को उपरोक्त मामले में विवादों की विवेचना करनी है।

यह सूचना दी जाती है कि आप आरोप-----को या उसके पूर्व रेल रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 29(1) के अंतर्गत उपरोक्त परिवार/आवेदन में प्रत्यक्ष विवाद काइल करेंगे।

और यह सूचना भी दी जाती है कि उपरोक्त परिवार/रेल रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 29 के उपविनियम (1) और उपविनियम (3) के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष जिसकी बैठक-----में आरोप-----को-----व्यक्ति-----होपी, सुनवाई और विवादों की विवेचना के लिए जाएगा।

यदि आप या आपका, और मैं आपका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो इस मामले को सुनवाई और इस पर विनिर्णय आपका अनुपस्थिति में ही दिया जाएगा।

आज यह आरोप-----को मंत्र हस्ताक्षर से आरंभ में 3, विक्टोरिया क्रिकेट ग्राउंड, मद्रास-105 में किया अधिकरण को मद्रास न्यायालय दिया गया है।

निर्वाह,

रेल रेट अधिकरण

परिशिष्ट 2

(प्रारूप 9)

[विनियम 33 (4) देखिए]

रेल रेट अधिकरण, मद्रास के समक्ष

19-----या परिवार/आवेदन सं.-----

-----परिवार/आवेदक

बनाम

-----प्रत्यर्थी

सेवा में

-----प्रत्यक्षी

आपके, तारीख-----के आवेदन पर, अधिकरण आपको रेल रेट अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 33 (1) के अधीन, बाह्य रूप प्रस्तुति की बाबत उपरोक्त परिवार/आवेदन (के समर्थन में/विरोध में) में संश्लेष करने की इजाजत देता है।

उक्त विनियम विनियम 33 (4) के अंतर्गत आप संलग्न परिवार/आवेदन की प्रार्थना के सात दिन के भीतर चाहें गए अनुसंधान के समर्थन में/विरोध में अपने आधिकारी तथा सम्पूर्ण से हस्ताक्षरित, आपका एक विवरण उत्तरी-----अनियों सहित प्रस्तुत करें, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रत्यक्षी के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने मेंमें व्यतिक्रम करने पर अधिकरण उक्त परिवार/आवेदन पर आपको अनुपस्थिति में ही सुनवाई कर सकेगा :

इसके अतिरिक्त, याप यह भी प्रतीत की जाती है कि आप सूचना की तारीख आदि के लिए और अभिलेख पुस्तक तैयार करने की लागत के प्रभारों की पूर्ति के लिए अधिकरण के तम विवरण सहित अतिरिक्त रूप से 150 रूपय जमा करें और यदि प्राप्त मासिक वारं गे अनुसंधान के समर्थन में है अथ 250 रूपय की फीस भी दे। यह प्रत्यक्षी सचिव, रेल रेट अधिकरण, मद्रास के पक्ष में या तो तुरंत या धारावेग द्वारा या प्रधान लोकहित अधिकारी रेल, मद्रास के पक्ष में काम पोस्टल आर्डर या आर्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा विप्रेषित की जा सकती है।

यह आज तारीख-----को मेरे हस्ताक्षर से और सं. 3, विक्टोरिया क्रिस्ट रोड, मद्रास-195 स्थित अधिकरण की मुद्रा लगाकर दिया गया।

सचिव,
रेल रेट अधिकरण, ...
मद्रास

परिशिष्ट-2

(पृष्ठ 10)

(विनियम 33 देखिए)

रेल रेट अधिकरण, मद्रास के समक्ष

19-----या परिवार/आवेदन सं.

-----परिवार/आवेदक

बनाम

सेवा में,

-----परिवार/आवेदक/प्रत्यर्थी/प्रत्यक्षी

यह सूचना दी जाती है कि इस मामले में पहल में ही विवरण के आधारों पर उपरोक्त आवेदन अधिकरण के समक्ष-----में तारीख-----को-----जाने-----की जायेगी।

यदि आप या आपको और से आपका कोई प्रतिनिधि, आपके साक्ष्यों सहित, उपस्थित नहीं होता है तो इस मामले पर सुनवाई और उर पर विनिश्चय आपकी अनुपस्थिति में ही किया जाएगा।

यह आज तारीख-----को मेरे हस्ताक्षर से और सं. 3, विक्टोरिया क्रिस्ट रोड, मद्रास-195 स्थित अधिकरण की मुद्रा लगाकर दिया गया।

सचिव,
रेल रेट अधिकरण।

नोटिफिकेशन

(संख्या 111)

(विनियम 35 के तहत)

रेलवे अधिकरण, मद्रास के समक्ष

1990-91 का परिवार/आवेदन सं.

.....परिवार/आवेदन

बनाम

.....प्रत्यर्थी

जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति ।

अधिकरण यह समझता है कि इस मामले में स्थानीय जांच अपेक्षित है । अतः आपसे रेलवे अधिकरण विनियम, 1990 के विनियम 35 के तहत
के प्रयोजनार्थ संबंधित पक्षकारों को अधिसूचित करने के पश्चात् ऐसी जांच करने और उस पर एक नोटिफिकेशन
को या 'उम्मेदवार' द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

किसी ऐसे माधो को आपके समक्ष हाजिर करना, जिसकी आप परीक्षा करना चाहते हैं या किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करना, जिसका आप निरीक्षण
 करना चाहते हैं, के लिए आदेशिका, अधिकरण द्वारा आपके आवेदन पर हो जारी की जाएगी । अधिकरण आपसे रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् आपके पालि-
 श्रमिक और व्यर्थों के संदाय का आदेश देगा ।

यह आज तारीख-.....को मेरे दस्तावेज से और सं. 3, बिकेटोरिया क्विंटेट रोड, मद्रास-600105 स्थित अधिकरण को भेजा जाकर
 दिया गया ।

सचिव,

रेलवे अधिकरण,

मद्रास

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1990

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 48 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and in supersession of the Railway Rates Tribunal Rules, 1959, read with Section 22 of the General Clauses Act 1897 (10 of 1897) the Railway Rates Tribunal, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

RAILWAY RATES TRIBUNAL (PROCEDURE) REGULATIONS, 1990

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Railway Rates Tribunal (Procedure) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Act.

2. Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(b) 'Appendix' means Appendix to these Regulations;

(c) 'applicant' means the Railway Administration making application under section 45;

(d) 'Chairman' means Chairman of the Tribunal;

(e) 'Code' means the code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);

(f) 'complainant' means a person making a complaint under Section 36;

(g) 'intervener' means any person allowed to intervene in a proceeding with the leave of the Tribunal.

(h) 'Member' means Member of the Tribunal;

(i) 'pleading' means a complaint under Section 36, an application under Section 45, the answer to any of these by the respondent, a reply to the answer wherever allowed or directed by the Tribunal and includes the grounds of support or objections, as the case may be, filed by an intervener;

(j) 'proceeding' means proceeding before the Tribunal;

(k) 'reference' means a reference to the Tribunal by the Central Government under Section 39;

(l) 'representative' means any person duly authorised in writing and includes a legal practitioner within the meaning of Advocates Act, 1961 (25 of 1961):

- (u) 'respondent' means any person impleaded as a party in a complaint under Section 36 or in an application under Section 45;
- (v) 'Secretary' means the person who for the time being is discharging the functions assigned under these Regulations and such other functions as may from time to time be directed by the Tribunal and includes an Assistant Secretary and any other officer appointed by the Tribunal to discharge the functions of the Secretary;
- (w) 'section' means a section of the Act;
- (x) 'Tribunal' means the Railway Rates Tribunal constituted by the Central Government under section 33;
- (y) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;
- (z) words and expressions used herein and not defined either in these Regulations or in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897);

3. **Typographical specifications.**—All pleadings, affidavits and interlocutory applications and copies thereof presented to the Tribunal shall be typewritten or printed fairly and legibly on substantial white foolscap folio paper, with a left hand margin at least 4 cm wide and a right hand margin about 2.5 cm wide, and separate sheets shall be stitched together. The type-script or printing shall be on one side only of the paper, and be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sums and numbers shall be mentioned expressly in figures.

4. **Appointment of Representative.**—(1) A party to the proceeding may appoint, in writing, any person as his representative to appear, act and be heard on all occasions before the Tribunal:

Provided that such appointment shall take effect only from the date on which the appointment order is filed with the Secretary:

Provided further that no Member of the Tribunal who has held office as such member shall be appointed as a representative.

(2) Any such appointment or terms of appointment of representative may be revoked or varied by the party appointing him by a declaration in writing:

Provided that such revocation or variation shall not take effect unless it is filed with the Secretary.

(3) The provisions of Order III of the First Schedule of the Code shall, insofar as may be, apply to the representatives.

5. **Authentication of documents, appearance and acting.**—A document may be signed, appearance made or act done:

- (a) in the case of a firm, by any of its partners;
- (b) in the case of a body corporate, association or authority, by its Chairman, President, Managing Director, General Manager or Secretary, as the case may be;
- (c) in the case of a railway administration, by the General Manager or the Chief Commercial Superintendent or any Head of the Department concerned of that railway administration; and
- (d) in the case of the Central Government, by a Secretary or a Joint Secretary or a Deputy Secretary or an Under Secretary to that Government and in the case of Ministry of Railways (Railway Board) by the Secretary or the Joint Secretary or the Deputy Secretary or an Executive Director or a Director, Joint Director or Deputy Director in the Railway Board.

6. **Verification.**—(1) Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties to the pleading or by some other person proved to the satisfaction of the Tribunal to be acquainted with the facts of the case.

(2) The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies on his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true.

(3) The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed.

(4) Where the verification is by some person other than the party, his name and address shall be given underneath his signature.

7. **Presentation.**—Unless otherwise specially provided, all pleadings and documents, applications and communications intended for the Tribunal shall be presented to the Secretary at the Headquarters of the Tribunal or despatched to him by registered post acknowledgement due.

8. **Time for presentation.**—(1) Pleadings and other documents, required or directed to be filed within a certain time, shall be filed at the Tribunal's office within that time.

(2) The date of receipt at the office of the Tribunal shall be taken as the date of filing.

9. **Service of notice and summons.**—(1) Unless otherwise directed by the Tribunal or the Secretary, notices and summonses to the parties or witnesses as the case may be, shall be served by registered post acknowledgement due to the address furnished to the Tribunal.

(2) A notice to a party may also be served on the representative.

10. Initiation of proceeding.—Every proceeding before the Tribunal shall be initiated by a complainant under section 36 or by an application under section 45 or by a reference under section 39.

11. Complaint.—(1) A complaint under section 36 shall be addressed to the Tribunal and shall be in writing signed and verified. It shall set out the name, description and full address of the complainant and, if there is a representative for the complainant in the matter, his name and full address shall also be stated.

(2) The complaint shall contain a clear and concise statement of facts, the grounds of complaint, the relief or remedy which the complainant claims and, where a person other than a railway administration is sought to be impleaded as a respondent, it shall also set forth the grounds for impleading him.

12. (1) Joinder of complainants.—Two or more persons having the same interest in the proceeding may join in a complaint, in which case all subsequent proceeding shall be in their joint names.

(2) Where there are more complainants than one, they shall nominate in the complaint either one of the complainants or his representatives as the person on whom any summons or notice may be served for and on behalf of all the complainants.

13. Respondent.—(1) Where a complaint is made against a railway administration such railway administration shall be impleaded as the respondent.

(2) Where the complainant has reason to believe that any other person is likely to be materially affected by the relief he is seeking, such person shall also be impleaded as a respondent.

(3) The name, description and address of the respondent shall be given in the complaint and, where a railway administration of the Government railway is the respondent, the provisions of section 79 of the Code shall apply.

14. Copies of complaint.—Every complaint shall be accompanied with twice as many copies as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

15. Fee and deposit.—With each complaint, the complainant shall pay a fee of Rs. 250/- and provisionally deposit of Rs. 150/- to meet the charges of the service of notices and other processes and cost of preparation of paper book.

16. Scrutiny and registration of Complaint.—(1) On receipt of a complaint the Secretary shall mark on it the date of its receipt and initial it, and he shall thereafter endorse on it a report whether prima facie the complaint is or is not within the jurisdiction of the Tribunal.

(2) Where the Secretary endorses that the complaint is not within the jurisdiction of the Tribunal he shall lay his report before the Tribunal for orders.

(3) Where a complaint is not in accordance with these regulations or is not accompanied with the necessary fee or deposit, and the complainant does not rectify the defect within the time allowed by the Secretary, the Secretary shall lay it, as soon as possible, before the Tribunal for orders.

(4) The Secretary shall give to the complaints filed, serial numbers according to the order in which they are received by him and enter them in a register specified in Form I of Appendix II.

17. Return of complaint.—(1) Where the Tribunal is of the opinion that a complaint is prima facie beyond its jurisdiction, it shall direct the Secretary to return the complaint with an endorsement to that effect.

(2) If within 30 days of the receipt of such endorsement, the complainant makes an application to be heard on the question of jurisdiction, the Tribunal shall decide the question after hearing the complainant and such other party as it may consider proper.

(3) The fee paid by the complainant shall be refunded to him if the complaint is returned to him as a result of an order passed under sub-regulation (1).

18. Adding and striking out parties.—(1) The Tribunal may, at any stage, either upon or without the report of the Secretary or the application of either party, and on such terms as may appear to the Tribunal to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as complainant or respondent, be struck out, or that the name of any person who ought to have been joined, whether as complainant or respondent, or who may be materially affected by the relief asked for, or whose presence before the Tribunal is considered proper or necessary for adjudication upon the questions involved in the complaint, be added;

1. Provided however that no person shall be added as a complainant without his consent.

(2) No proceeding shall be defeated by reason merely of misjoinder or non-joinder of parties.

(3) When respondents are added, the complaint and the register shall be accordingly amended; and the complainant shall also file such number of additional copies of his complaint as is equal to twice the number of respondents added.

19. Service notice of complaint.—(1) A copy of the complaint shall be served on each respondent with the seal of the Tribunal and an endorsement by the Secretary requiring the respondent to file his answer to the complaint within 30 days from the date of service, and also stating that, in default of such answer being filed within the said period, the Tribunal may proceed to hear the complaint in his absence and also stating that in such a case, the respondent will not be heard except by leave of the Tribunal and subject to such terms as the Tribunal may deem fit to impose.

(2) In the case of a railway administration, the copy may be served on the General Manager of the railway concerned.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, a public notice shall also be published, at the cost of the complainant and in the manner ordered by the Secretary of the Tribunal, mentioning the filing of the complaint, names of the parties, brief description of its allegations and relief sought, and calling upon any person wishing to intervene in support of or opposition to the relief sought in the complaint to petition the Tribunal within 30 days of publication of the notice for leave to intervene.

(4) If it is considered that there are persons who are not on the record but have the same interest in the proceeding as the complainant or respondent, that fact should be mentioned in the public notice, and any decision given by the Tribunal after such public notice shall apply to all such persons.

20. Withdrawal of complaint.—(1) The complainant may at any stage after the institution of the complaint withdraw his complaint, and in that case the Tribunal may pass such orders, including orders as to costs, as it may deem fit.

(2) In the case of withdrawal of complaint before the answer is filed, the fee paid by the complainant shall be refunded.

21. Compromise of complaint.—When any complaint is adjusted by a compromise between the parties, both of them shall immediately notify the Tribunal of the same, and the Tribunal shall, after such notice, if any, as it may consider necessary, pass suitable orders disposing of the complaint.

22. Answer.—(1) The answer shall admit or deny specifically each allegation of fact contained in the complaint and not by a general denial of the grounds alleged by the complainant, and, unless denied specifically or by necessary implication, an allegation of fact in the complaint shall normally be taken as admitted by the respondent. The answer shall contain a clear and concise statement of the material facts on which the respondent relies and shall raise all grounds of defence.

(2) The answer shall be divided into paragraphs numbered consecutively and signed and duly verified and it shall set out the name, description and full address of the respondent and, if there be a representative acting for the respondent in the matter, his name and full address shall also be stated.

(3) Every answer shall be accompanied with twice as many copies as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal, and a sum of Rs. 150 shall also be deposited to meet the charges of service of notice and other processes and the cost of preparation of paper book.

23. Scrutiny and service of Answer.—(1) On receipt of an answer, the Secretary shall mark on it the date of its receipt and initial it.

(2) If the answer is not in accordance with these regulations, or is not accompanied with the necessary deposit, and the respondent does not rectify the

defect within the time allowed by the Secretary, the Secretary shall lay it as soon as possible before the Tribunal for orders.

(3) Copies of the answers received from the respondents shall be sealed and initialled by the Secretary and served on the complainant and on such other party as the Tribunal may order.

24. Subsequent pleading.—No pleading subsequent to the answer shall be presented except by the leave of the Tribunal and upon such terms as the Tribunal may deem fit, but the Tribunal may at any time require from any of the parties a reply or additional reply together with twice as many copies thereof as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal and fix a time for presenting the same.

25. Amendment of pleading.—The Tribunal may at any stage allow any pleading to be amended, or order any matter to be struck out which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair hearing of the case, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions at issue between the parties.

26. Production of Documents.—(1) Unless for good cause shown and on such terms as the Tribunal may deem fit, all documents in possession of a party on which he wishes to rely at the hearing shall be produced by him, along with the list thereof, on or before such date as may be fixed by the Tribunal for the purpose. He shall file at the same time, as many copies of the documents as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

(2) The Tribunal may, at any time, order the production by any party of such of the documents in his possession or power relating to the matters in question as it may deem fit.

27. Interrogatories and discovery.—Any party to the proceeding may apply to the Tribunal for leave to deliver interrogatories in writing for examination of the opposite party, or for an order directing the opposite party to make a discovery of the documents in his possession, and in either case the provisions of order XI of the first schedule of the Code as far as may be, shall apply and such applications may be rejected if they are so delayed as to necessitate an adjournment of the hearing of the case.

28. Inspection of documents.—(1) Either party shall be entitled at any time to give notice to the other party, in whose pleadings or affidavits reference is made to any document, to produce such document for the inspection of the party giving such notice, and to permit him to take copies thereof and the party not complying with such notice shall not afterwards be at liberty to put any such document in evidence on his behalf, unless he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not complying with such notice.

(2) All books, documents and other things produced before the Tribunal, whether voluntarily or on requisition, may be inspected by the parties.

Provided that Tribunal may in its discretion refuse publication of such parts of the books, documents or things produced as the parties may submit to be prejudicial to their interests to publish.

29. Framing of issues.—(1) After the closure of the pleading and the filing of documents, the Tribunal shall call upon the parties or representatives to furnish the draft issues.

(2) The Tribunal shall thereupon frame the issues.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before it or without the inspection of some documents not produced, it may, subject to any law for the time being in force, compel the attendance of, or the production of any document, by any person.

30. Examination of parties before hearing.—The Tribunal may, before the hearing of the complaint examine the parties or their representatives for the purpose of considering :—

- (a) the simplification, narrowing down or adjustment of matters in issue between the parties;
- (b) the admission or denial by each party of the documents of the others ;
- (c) the limitation of the number of witnesses ;
- (d) the procedure at the hearing ; and
- (e) such other matters as may aid in the speedy disposal of the complaint.

31. Amendment of issues.—At any time before giving its decision, the Tribunal may amend the issues or frame additional issues, as it thinks, fit, or may be necessary, for determining the matters in dispute between the parties, and it may strike out any issue that appears to it to be wrongly framed.

32. Intervener.—(1) On the public notice given under sub-regulation (3) of regulation 19 any person may within the time prescribed in the said sub-regulation petition the Tribunal for leave to intervene in support of or in opposition to the relief sought for in the complaint.

(2) A petition for leave to intervene must set forth the grounds of the proposed intervention, the position and interest of the petitioner in the proceeding, and whether the same is in support of or opposition to the relief sought.

(3) It shall be within the Tribunal's discretion to grant or reject such leave in the light of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 18 relating to addition of parties.

(4) If leave is granted, the petitioner shall be unpleaded as intervener and notified of the same, and, within 7 days of receipt of such notice, he shall file his pleading which shall conform to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 11 or sub-regulation (1) of regulation 22, as the case may be. He shall also deposit at the same time Rs. 150/- to meet the

cost of service of notice, other processes and the cost of preparation of paper book and a sum of Rs. 250 if he intervenes in support of the complaint. He shall file twice as many copies of his pleadings as there are parties and three additional copies for the use of the Tribunal.

33. Date of hearing.—After the settlement of the issues the Tribunal shall fix a day, time and place for the hearing of the complaint and communicate the same to the parties concerned.

34. Right of audience.—(1) Any party to a proceeding before the Tribunal shall be entitled to be heard either in person or by his representative.

(2) The Tribunal may permit any person likely to be of assistance to address the Tribunal.

35. Local inquiry and report.—In any proceeding in which the Tribunal deems a local inquiry to be requisite or proper, it may appoint any Railway Officer not below the rank of an Assistant Officer to hold a local inquiry after notice to the parties and to report thereon to the Tribunal. The receipt of the report may be communicated to the parties for filing their objections, if any after making an inspection of the report, within the time fixed, and the Tribunal shall dispose of these objections :

Provided that it may refuse to consider, any objections not filed within the said time. The report shall be treated as part of the evidence in the case. The provisions of Order XXVI of the First Schedule to the Code shall apply as far as may be, to such local inquiries and reports.

36. Commission.—The Tribunal may at any stage of the proceeding issue a commission for examination of witnesses. The provisions of Order XXVI of the Code shall apply as far as may be to the commissions issued under this regulation.

37. Summons to witnesses.—(1) A party who desires to summon a witness for appearance before the Tribunal or before a Commissioner appointed under regulation 36, shall at least 30 days before the date of hearing, produce a list of persons whose attendance is required, stating the full name, description and address of each person and whether he is required to give evidence as an expert or otherwise or to produce documents, and, in the last mentioned case, specifying the date, if any, and the description of the documents so as to identify them. He shall with such a list deposit the total amount of the allowances to which the said persons are entitled for travelling and attendance before the Tribunal, calculated in accordance with the Rules of the High Court of Judicature at Madras in its ordinary original civil jurisdiction.

(2) Whenever the Tribunal deems it necessary, it may, of its own motion, summon any person to give evidence, or to produce any document in his possession, and pass necessary orders as to the costs of summoning such person.

(3) Witnesses shall be served with summonses in accordance with sub-regulation (1) of regulation requiring them to attend or to produce a document at the time and place fixed. If a witness so served fails to attend as required, his attendance may be enforced by recourse to the provisions of Order XVI of the First Schedule to the Code.

38. Further evidence.—The Tribunal may, at any stage of the hearing, call for further evidence on any issue from any party.

39. Preliminary questions of law.—The Tribunal, may, with consent of the parties to any proceedings, or on the application of any party, or of its own motion, order any point of law raised by the pleadings to be set down for hearing and to be disposed of at any time before the hearing of the complaint. If, in the opinion of the Tribunal, the decision on such point of law substantially disposes of the whole complaint, the Tribunal may make such order as may seem to it to be just and proper.

40. Hearing.—(1) Every complaint shall be heard in open Court at the time and place fixed by the Tribunal.

(2) The hearing shall proceed from day to day as far as in the judgment of the Tribunal may be practicable and convenient, and the same shall not be adjourned at the instance of a party except for reasons considered sufficient by the Tribunal and on such terms, including payment of costs, as the Tribunal may deem fit.

41. Default of appearance.—If the complainant does not appear at the time and place appointed for hearing, the Tribunal may dismiss the complaint or, at its discretion, proceed with the hearing at the instance of an intervener supporting the complaint, and if the respondent does not likewise appear, it may hear and decide the complaint in his absence. If at any adjourned date of the hearing the parties or any of them do not appear, the Tribunal may dismiss the complaint or decide it 'ex parte', as the case may be, or it may dispose of the case in their absence.

42. Re-hearing.—(1) When a complaint is dismissed for default, but the complainant satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for default, the order of dismissal may, after notice to the opposite party, where necessary, be set aside and the complaint proceeded with upon such terms as to costs or otherwise as the Tribunal may deem fit.

(2) When an 'ex parte' decision has been made, but the respondent satisfies the Tribunal that notice was not duly served on him, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing, the 'ex parte' decision may be set aside and the case proceeded with upon such terms as to costs or otherwise as the Tribunal may deem fit.

(3) An application for setting aside an order of dismissal of complaint or an 'ex parte' decision shall be made within 30 days of the dismissal of the complaint or the passing of the 'ex parte' decision, as the case may be, unless the Tribunal condones the delay for adequate reasons.

43. Act 1 of 1872 to apply.—The provisions of the Indian Evidence Act 1972 (1 of 1872) shall as far as may be, apply to the proceedings:

Provided that the Tribunal may in its discretion, without prejudice to the rights of the parties relax any of its provisions, for securing the necessary evidence inexpensively and expeditiously.

44. Affidavit.—(1) The evidence at the hearing of a complaint may be taken either by affidavit or viva voce, or partly by affidavit and partly by viva voce;

Provided that if either party intends to rely on any evidence by affidavit, he shall, at least 10 days before the hearing, deliver or send by registered post to the other party a copy of the affidavit intended to be used, failing which he shall not be allowed to use the same except by special leave of the Tribunal.

(2) Either party may, within 7 days after receipt of a copy of any affidavit intended to be so used, deliver or send, by registered post to the other party, a notice requiring the deponent to be produced at the hearing of the complaint for cross-examination, and unless the deponent is so produced, his affidavit shall not be used except by special leave of the Tribunal.

(3) The Tribunal may at any time for sufficient reason, order that any particular fact may be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the Tribunal deems reasonable:

Provided that where it appears to the Tribunal that either party bona fide desires the production of a witness for cross-examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorising the evidence of such witness to be given by affidavit.

(4) An affidavit shall be confined to such facts as the witness is able of his own knowledge to prove, except in interlocutory proceedings, in which statements as to his belief with the grounds thereof may be admitted.

(5) For the purpose of any affidavit to be sworn in any proceeding before the Tribunal, the Chairman may empower any official of the Tribunal to administer an oath to the deponent of the affidavit.

45. Oral evidence.—(1) The oral evidence of a witness shall be taken down in the open court in English under the direction of the Tribunal and the Typewritten copy shall be initialled by the Chairman or by any Member of the Tribunal.

(2) When evidence is given by a witness in a language other than English, the Tribunal may appoint an interpreter who shall take oath or solemnly affirm that he will render the evidence into English correctly. The interpreter shall be paid such fees as may be directed by the Tribunal.

46. Judgment.—(1) The Tribunal after hearing and considering the evidence and arguments shall, give its decision, either at once or as soon thereafter

as may be practicable on some future day; and when the decision is to be pronounced on some future day, the Tribunal shall fix a day for that purpose, of which due notice shall be given to the parties or the representatives.

(2) The decision shall be signed by the Chairman and the Members of the Tribunal, and a copy of the operative part of the decision shall be made available to each party.

47. Costs.—(1) The Tribunal may in its discretion order payment of costs of the proceedings by either party to any other, either in whole or in part. The fact that the Tribunal has no jurisdiction in respect of the proceedings shall be no bar to the exercise of such powers.

(2) The scale of fees admissible for the award of costs for and in connection with the proceeding before the Tribunal shall be as shown in the Appendix I.

(3) The bill of costs shall be prepared by the Secretary and attached to the decision of the Tribunal, and a copy thereof shall be sent to the parties. The bill of costs may be corrected by the Secretary or the Tribunal at the instance of any party, if it be necessary to do so.

48. Change in Personnel of Tribunal.—Where the Tribunal is prevented by a change in its personnel from concluding any proceedings before it the succeeding re-constituted Tribunal may resume the same from the stage at which the previous Tribunal left it, and it may give a decision, or submit a report, written but not given or submitted by its predecessor, and correct the bill of costs relating to a decision given by its predecessor.

49. Rectification of errors.—Clerical or arithmetical mistakes in any decision or order of the Tribunal, or errors arising therein from any accidental slip or omission, may at any time be corrected by the Tribunal either of its own motion or on the application of any of the parties.

50. The Tribunal may at any time, and on such terms as to costs or otherwise as it deems fit, amend any defect or error in any proceedings before it and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question at issue raised by or depending on such proceedings.

51. Interlocutory orders.—The Tribunal may pass, vary or set aside, after hearing or 'ex parte' such interlocutory orders, including temporary injunctions, as may be necessary.

52. Enlargement or abridgement of time.—The Tribunal may enlarge or abridge the time limit for doing any act or taking any proceeding upon such terms as the justice of the case may require.

Provided that the period prescribed for applying for setting aside an order of dismissal of complaint or an 'ex parte' decision, shall not be abridged.

53. Computation of time.—In all cases in which a particular number of days is prescribed by these regulations or in an order passed by the Secretary or the Tribunal, the same shall be reckoned exclusively of the first day and inclusively of the last day, and if the office of the Tribunal is closed on the last day, the time shall be reckoned exclusively of that day also. If on any day on which an act is required to be done by a party and the office is closed on that day, it may be done on the day on which the office next opens.

54. Application, under Sections.—These regulations shall as far as may be, apply to the disposal of cases where a railway administration is an applicant under section 45.

55. Reference.—A reference to the Tribunal for inquiry and report shall be in the form of a letter addressed to the Secretary of the Tribunal and sent by registered post. The letter shall specify, inter alia,

- (a) the details of the matter referred to the Tribunal for inquiry and report; and
- (b) all information in the possession of the Central Government which that Government may think relevant to the matter before the Tribunal.

56. Public notification of inquiry.—The Tribunal may, at any stage, publish a notification, either generally about the inquiry or about any of the proceeding in connection therewith, to enable the trades or trade associations or persons interested in the matter to submit their memoranda or offer oral evidence at the inquiry.

57. Public inquiry.—At the discretion of the Tribunal, a public inquiry may be held at a time and place announced by public notification.

58. Report of the inquiry.—The report of the inquiry shall be submitted to the Central Government, and that Government may, if it thinks fit, release it to the public.

59. Commissions for inquiry.—For purposes of inquiry, the Tribunal may issue such commissions and summon such witnesses as it may consider necessary.

60. Paper books.—In every case relating to a complaint or an application there shall be prepared typed paper books of the pleadings, issues, evidence recorded, documents admitted and such other parts of the record as may be specifically ordered to form part of the paper book. As many copies of such paper books shall be prepared as may be required for the Members of the Tribunal and the parties. Cost of preparation of paper books shall be charged at Rs. 1.75 per page in respect of such matter as may be typed in the office of the Tribunal.

61. Working hours of the Tribunal.—Except on Saturdays, Sundays and other Public holidays and subject to any order made by the Chairman, the working hours of the Tribunal shall be from 10.30 AM to 1.30 PM and 2.15 PM to 4.30 PM and that of the office of the Tribunal shall be from 10.00 AM to 1.30 PM and 2.00 PM to 6.00 PM.

62. Holidays and Vacations.—The Tribunal may observe the same holidays and vacations as that of the Madras High Court :

Provided that the office shall remain open during the vacation and transact its normal business :

Provided further that no extension of time shall be granted merely on the ground that the Tribunal was closed for vacation.

63. Return of documents (1) Documents admitted in evidence may after the disposal of the proceedings be returned to the party concerned either by being delivered to him in person or sent to him by registered post acknowledgement due, or by parcel at his risk and cost :

Provided that a document admitted in evidence may be returned earlier if the party applying therefore, delivers to the Secretary a

certified copy to be substituted for the original and undertakes to produce the original if required to do so.

(2) Where a document is returned to a party by its being delivered to him, a receipt shall be given by the person receiving it.

(3) Documents not admitted in evidence shall not form a part of the record and shall be returned to the parties respectively producing them in the manner provided in sub-regulation (1).

64. Certified copies of record.—Unless specially ordered otherwise by the Tribunal, a party to a proceeding shall be entitled to have certified copies of any part of the record of the proceeding. Such certified copies shall be prepared in the office of the Tribunal and charged at the rate at which certified copies are charged in the Madras High Court.

65. Remittance.—All monies to be paid to or deposited with the Tribunal shall be paid in cash at the office of the Tribunal or remitted by money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

66. Refund or recovery against deposit.—After the conclusion of a case, the Secretary shall calculate the amount spent out of the deposit made by each party and either return to him the excess or recover from him the deficit, as the case may be.

67. Forms and registers.—The notices to be served and registers and other records to be maintained in the Office of the Tribunal shall be as specified in Appendix II.

68. Rules of practice of Madras High Court.—The rules of practice of the Madras High Court, in so far as they are not inconsistent with the Act and these regulations, may in the discretion of the Tribunal be followed.

69. Court seal.—The seal of the Tribunal shall be kept in the custody of the Secretary.

[No. TC-I/89/216/21]

K. RAJAGOPALAN, Asstt. Secy.,
Railway Rates Tribunal

APPENDIX- I

[See regulation 47(2)]

Scale of fees for award of costs in connection with proceedings before the Tribunal.

	Rs.
For filing a complaint under Section 36/an application under Section 45 or for intervening in support of a complaint	250.00
For vakalatnama	5.00
For filing any other application	3.00
For service of notice, summons	5.00 or the actual cost whichever is more.
For service of interrogatories	5.00
For filing any affidavit made outside the Tribunal	5.00
For injunction petition	10.00
For making an affidavit before an Officer of the Tribunal/Court	5.00

APPENDIX-II

FORM-I

REGISTER OF COMPLAINT FOR THE YEAR.....

[See regulation (16) 4]

Sl. No.	Date of complaint and its receipt	Date of registration	Date of complaint	Name of respondent	Subject matter	Name of intervener
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date of judgement	Operative part of judgement	Date of communication of the operative part to parties	Writ to High Court, Appeal to Supreme Court or correction and result	Miscellaneous Application, if any
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

APPENDIX II

FORM II

REGISTER OF APPLICATIONS FOR THE YEAR

[See regulation 16(4) and regulation 54]]

Sl. No.	Date of application and its receipt	Date of registration	Name of applicant	Name of Respondent	Cross reference to Original proceedings	Name of intervener
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date of judgement	Operative part of the judgement	Date of communication of operative part to parties	Miscellaneous Application, if any.	Remarks.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

APPENDIX-II

FORM-III

REGISTER OF MISCELLANEOUS/INTERLOCUTORY APPLICATIONS FOR THE YEAR.....

(See regulation 51)

Sl. No.	Date of application and its receipt	Date of registration	Name of the applicant	Name of the respondent	Subject matter	Cross references to the Original complain/application
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Name of the intervener	Date of the order	Nature of the order	Date of communication of the order to the parties.	Remarks
(8)	(9)	(10)	(11)	(x2)

APPENDIX-II
(FORM-IV)

REGISTER OF REFERENCES FOR THE YEAR.....

(See Regulation 55)

Sl. No.	Particulars of reference and date of its receipt	Date of registration	Subject matter of reference	Date of Report of the Tribunal	Recommendation	Date of despatch of the Report	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

APPENDIX-II
(FORM-V)

(See regulation 18)

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL
AT MADRAS

COMPLAINT NO.....OF 19.....

COMPLAINANT

Vs.

RESPONDENT

To

Whereas.....has instituted the above complaint against.....forand whereas it appears proper or necessary that you should be added as a complainant in the said matter in order to enable the Tribunal to adjudicate upon and settle the questions involved in the complaint.

Take notice that under Regulation 18 of the Railway Rates Tribunal Regulation 1990, you are required on or before the.....day of.....19.....to signify to this Tribunal whether you consent to be so added.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19.....at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras 105.

Sd/-
Secretary,
Railway Rates Tribunal

APPENDIX-II
(FORM-VI)

(See regulation 19)

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL
AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....OF 19.....

COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

RESPONDENT

TO

RESPONDENT

Under Regulation 19(1) of the Railway Rates Tribunal Regulations 1990, you are hereby required within 30 days from the date of service upon you of the enclosed complaint/application to put in your answer to the same together with.....copies and to take notice that in default of such answer being put in within the said time, the Tribunal may proceed to hear the said complaint/application in your absence.

Your answer and the copies thereof may be presented to me at my office at the headquarters or sent to me by Registered post. You should also make a provisional deposit of Rs. 150/- to meet the charges of service of notice, etc. and preparation of paper book. The amount may be remitted either in cash /money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or by means of crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19.....at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-105.

Secretary
Railway Rates Tribunal

APPENDIX-II

(FORM -VII)

[See regulation 19(3) & (4)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL

AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO. OF 19 .

.....COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

.....RESPONDENT

Whereas the complainant/applicant above named has made a complaint/application that.

And, whereas, it is thought that there are numerous persons who are not on record but have the same interest in the proceedings as the complainant/applicant or respondent above named.

This public notice is, therefore, given under Sub-regulations (3) and (4) of Regulation 19 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, so that any person who so desires may petition the Tribunal within 30 days of the publication of this notice for leave to intervene in support of or opposition to the relief sought in the complaint/application or be added on the side of the complainant /applicant or the respondent, setting forth the grounds of the proposed intervention and the position and the interest of the petitioner in the proceedings on the grounds for being added as a party in the said case.

Any decision given by the Tribunal after such public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19. at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary,
Railway Rates Tribunal.

APPENDIX-II

(FORM-VIII)

[See regulation 29(2)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL

AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO. OF 19 .

.....COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

.....RESPONDENT

To

.....COMPLAINANT/APPLICANT/RESPONDENT/INTERVENER

Whereas the Tribunal has to frame issues in the above case.

Take Notice that you shall file the draft issues in the above complaint under regulation 29(1) of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, on or before.....day of.....19 .

And also take notice that the above complaint will come up for hearing and framing issues before the Tribunal, in accordance with sub-regulations (2) and (3) of regulation 29 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, sitting atOn the.....day of.....19.....atO'clock in the.....noon.

If no appearance is made on your behalf by yourself or your representative, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 . at No. 3 Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary,
Railway Rates Tribunal.

APPENDIX-II
(FORM-IX)

[See regulation 32(4)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL
AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....of.....19 .

.....COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

.....RESPONDENT

TO

.....INTERVENER

On your application, dated.....under Regulation 32(i) of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990, you have been granted leave by the Tribunal to intervene in the above complaint/application (in support of/in opposition) to the relief sought.

Under Regulation 32(4) of the said Regulation, you are hereby required within 7 days of the date of receipt of the enclosed complaint/application, to put in your statement of grounds in support of/in opposition to the relief sought, duly signed and verified, together withcopies thereof, and to take notice that in default of such statement being put in within the said period, the Tribunal may proceed to hear the said complaint/application in your absence.

Further, you are hereby called upon to make along with your statement a provisional deposit of Rs. 150/- with the Tribunal to meet the charges for the service of notice, etc., and cost of preparation of paper book, and, as your intervention is in support of the relief sought, also a fee of Rs. 250/- . The amount may be remitted either in cash/money order in favour of the Secretary, Railway Rates Tribunal, Madras or by means of crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier, Southern Railway, Madras.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 . at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Sd/-

Secretary
Railways Rates Tribunal
Madras.

APPENDIX-II
(FORM-XI)

[See regulation (33)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL
AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO.....OF.....19 .

.....COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

.....RESPONDENT

TO

.....COMPLAINANT/APPLICANT/RESPONDENT/INTERVENER

Take notice that the above complaint/application will come up for hearing before the Tribunal sitting at.....on the.....day of.....19 . atO' Clock in thenoon, on the issues as already settled in this case.

If no appearance is made on your behalf by yourself or your representative....., along with your witnesses, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this.....day of.....19 at No. 3, Victoria Crescent Road, Madras-600105.

Secretary
Railway Rates Tribunal

APPENDIX-II

(FORM-XI)

[See regulation (35)]

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL

AT MADRAS

COMPLAINT/APPLICATION NO. OF 19

..... COMPLAINANT/APPLICANT

Vs.

..... RESPONDENT

TO,

The person appointed to hold the enquiry.

Whereas the Tribunal deems a local enquiry to be requisite in this case, you are hereby required to hold such enquiry under Regulation 35 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990 after notifying the parties concerned, for the purpose of and to submit your report on or before day of 19 .

Process to compel the attendance before you of any witness or for the production of any document whom or which you may desire to examine or inspect will be issued by this Tribunal on your application.

The Tribunal will order payment of your remuneration and expenses after it has received your report.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this day of 19 , at No. 3 Victoria Crescent, Road, Madras-600105.

Secretary,
Railway Rates Tribunal,
Madras